(b) if so, their number and the estimated annual amount involved in their cases?

The Minister of Rehabilitation (Shri Mehr Chand Khanna): (a) No.

(b) Does not arise.

स्पात समकारी निधि

८७. **श्री के० सी० सोखिया** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) स्पात समकारी निधि की स्थापना कब हुई थी;

(ख) इस निधि में कुल कितना धन जमा है; और

(ग) १९५१–५२, १९५२–५३, १९५३–५४ तथा १९५४–५५ में इस निधि में जमा किये गये तथा खर्च किये गये धन का ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और स्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) १ फरवरी, १९५३ ।

(ख) ४६,१४,९५,८१५ रु० ३१ मार्च, १९५५ तक ।

(ग) एक विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४७].

आकाशवाणी की पत्रिकायें

८८. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं में कोई विज्ञापन छपते हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक से औसतन मासिक आय क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी हां, अखिल भारतीय रेडियो के देशी कार्यक्रम पत्रिकाओं में विज्ञापन छपते हैं ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के मेज पर रख दी जायेगी ।

Housing Schemes

89. **Shri H. N. Mukerjee:** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state:

(a) the total amount provided for expenditure on Housing schemes of different categories in the First Five Year Plan period;

(b) the amount spent on that account up-to-date; and

(c) the steps taken or proposed to be taken for preventing lapse of amounts provided for this purpose?

The Minister of Commerce (Shri Karmarkar): (a) The total provision for Housing Schemes in the First Five year Plan is Rs. 38.5 crores. The plan does not indicate a disrtibution of this amount among different categories of Housing.

(b) The assistance sanctioned upto the end of June, 1955 amounts to over Rs. 39 crores. The actual disbursements made, however, amount to about Rs. 12·1 crores, as payments under the Subsidised Industrial Housing and Low-Income Group Housing Schemes are related to progress of construction.

(c) The State Governments have been requested to speed up implementation of their housing programmes so that as large a portion of the sanctioned amount as possible (upto a maximum of Rs. 38·5 Crores) could be actually disbursed to and utilised by them before the end of March, 1956 .

कुटीर तथा दस्तकारी उद्योग

९०. **श्री लक्ष्मीधर जेना** : क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कुटीर तथा दस्तकारी उद्योगों के विकास के लिये विभिन्न राज्यों को १९५२-५३ से १९५५-५६ तक कितना धन अनुदान तथा ऋण के रूप में अब तक दिया गया है ?

उत्पादन मंत्री (श्री क० सी० रेड्डी): जहां तक रेशम, दस्तकारी, खादी तथा ग्रामोद्योग का सम्बन्ध है एक विवरण सभा की टेबल पर रखा जा रहा है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५८]